Motion for consideration of Provisional Collection of Taxes Bill, 2023 (Motion adopted and Bill passed)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I rise to move :

?That the Bill to provide for the immediate effect for a limited period of provisions in Bills relating to the imposition or increase of duties of customs or excise, be taken into consideration.?

माननीय सभापति**:** माननीय मंत्री जी, अगर आप बिल पर कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Thank you, Sir. I will briefly highlight the need for a Bill of this nature. Article 265 of the Constitution provides that no tax shall be levied or collected except by the authority of law. What this Bill seeks to obtain is this authority from the Parliament to provisionally levy and collect the newly imposed or increased duty of the customs and excise for 75 days. I will briefly give you the background.

The Provisional Collection of Taxes Bill, 2023 which is before us proposes to replace the erstwhile Provisional Collection of Taxes Act, 1931 with just minor changes which are technical in nature. This law is in existence from 1931. We have just made minor changes and we are here, therefore, not with a new law but with a mildly amended existing law.

The provision of the Bill empowers collection provisionally ? I underline the word ? provisionally? ? during the period between the introduction and the enactment of the Bill the increased Customs or Central Excise Duty where such duty rate is increased beyond the statutory rate approved by the Parliament or where such duty is newly imposed. So, if we are bringing in something which has to be implemented from a particular date, this Provisional Collection of Taxes Act, which exists from 1931, is the one which gets invoked. This Bill confines this interim period to 75 days, and where the Bill is not enacted within 75 days or is enacted with amendments, the provisionally collected taxes are to be refunded. So, I would like to make it very clear that the amendments to this or rates increased by the

invocation of this particular Provisional Collection of Taxes Act, 1931 is valid only upto 75 days within which I need to make sure that it gets the approval of the Parliament. If it does not get the approval of the Parliament, then the amount collected will be refunded.

I already said that Article 265 of the Constitution provides that no taxes can be levied or collected except by the authority of law. So, if I do not have a law within 75 days, the amount collected becomes not valid and, therefore, it has to be repaid.

Why do we then at all need to collect temporarily? Why do we want to provisionally collect it and run the risk that if we do not pass the Bill, we will have to pay the refund back? Why do we want to do it? This provision is required for reasons such as to provide tariff protection to domestic industry on immediate basis. Sometimes you will have to bring it immediately, and not wait for 75 days or not wait for the Session to conclude, pass the Bill and so on. So, you want immediate relief to be given. When the prices are going up, you need to moderate it, avoid speculation in the market and also for revenue considerations.

This is not required in the Income-Tax. It is only required for the Indirect Taxes. In the case of Income-Tax, changes are made in the Finance Bill for the next Financial Year. So, on 1st February, I might bring in the Budget, and will announce it. But it gets effective only from 1st April. So, for the next Financial Year is when changes are made. Therefore, the power to collect tax provisionally is not required for income-tax. In the case of GST, all the rate changes are first of all carried out only based on recommendations of the GST Council. So, it gets decided in the Council, and then it comes here for the Central Government to pass it as a part of either Finance Bill or otherwise. On the recommendations of the GST Council the effective date of change of rate is also decided, and then it is synchronized between the Centre and the States. That is the case for the GST. Hence, the power to collect tax provisionally is not required for the GST. It is only, therefore, for the Customs and Excise Duties that we need it. So, I appeal to the House that this temporary provision which gives me the provisional power to collect taxes subject to the House passing the Bill continues with it, and if it does not within 75 days, I can pay back, helps me to stabilize the prices in the market, helps me to ensure that there are no speculations in the market, and above all helps me when I want to have immediate impact to protect the domestic industry. Thank you, Sir.

16.00 hrs

माननीय सभापति **:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

?कि सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क के अधिरोपण या उसमें वृद्धि से संबंधित विधेयक के उपबंधों को सीमित अवधि के लिए तुरंत प्रभावी करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए?

श्री जयंत सिन्हा **(**हज़ारीबाग**):** सभापति महोदय, आपको और मेरी पार्टी को आभार कि आपने इस प्रोविजनल कलैक्शन ऑफ टैक्सेज बिल पर बोलने के लिए एक अवसर दिया है ।

इस बिल के द्वारा जो दो-तीन मुख्य बातें हैं, मैं उन पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा । पहली बात तो यह है कि आज हम लोगों की जो अर्थव्यवस्था है, जो महान अर्थव्यवस्थाएं हैं, मेजर इकोनॉमीज़ हैं, उन सब में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है । आज हम लोगों की अर्थव्यवस्था 7 परसेंट से ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है और प्रधान मंत्री जी ने हम सब को आश्वासन दिया है कि अगर विश्व में हम लोग 5 वें स्तर पर हैं तो अगले कार्यकाल में, माननीय प्रधान मंत्री जी के अगले कार्यकाल में 5 वें स्तर से तीसरे स्तर पर आ जाएंगे । माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी की यह गारंटी है । हम लोग वह गारंटी इस विश्वास के साथ क्यों दे सकते हैं, इसलिए दे सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के निरंतर सुधार के लिए जो ठोस कदम हम लोगों को लेने हैं, ये ठोस कदम हम लोग निरंतर लेते चले जा रहे हैं । चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव्स हों, आयुष्मान भारत हो, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड हो, इन सब में हम लोगों ने बड़े-बड़े ठोस कदम लिए हैं, प्रभावशाली कदम लिए हैं । आज हम लोग सदन में जो चर्चाएं कर रहे हैं, पहले जीएसटी बिल पर की और अब प्रोविजनल कलैक्शन ऑफ टैक्सेस के बिल पर चर्चा कर रहे हैं ।

माननीय सभापति महोदय, इनके द्वारा हम लोगों को जो स्ट्रीमलाइनिंग करनी है, हम लोगों को जो रेशनलाइजेशन करना है, हम लोगों को जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, वह हम लोग दर्शा रहे हैं कि इसको किस तरीके से किया जाता है? जब हम लोग इस तरीके से निरंतर करते रहेंगे, सुधार लाते रहेंगे तो अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ेगी और हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर चली जाएगी । इन दोनों बिलों के द्वारा आपको यह समझना जरूरी है, सब माननीय सांसदों को समझना जरूरी है कि यह काम डायनेमिकली चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है । इसका प्रभाव देखिये, हम लोगों ने जो इनडायरेक्ट टैक्सेज में, अभी तो जीएसटी की बात हुई, अब हम कस्टम और एक्साइज की बात कर रहे हैं, हम लोग जो इनडायरेक्ट टैक्सेज में सुधार लाए हैं, जिसके द्वारा इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारी इकोनॉमी में हुआ है । यह दूसरी मुख्य बात है । मैं कुछ आंकड़ों के द्वारा फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी के बारे में आपको बताना चाहता हूं । अभी बात हुई कि जहां करीब 44 लाख लोग जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेज भर रहे थे, अब वह संख्या 1.4 करोड़ लोगों की हो गई है । कलैक्शंस का इंक्रीज भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जीएसटी के द्वारा 1 लाख 86 हजार लोगों का कलैक्शन होने लग गया है । आप देखें कि टैक्स पेयर्स कितने हो गए हैं? वे भी उसमें दोगुने हो गए हैं, जहां 3.79 करोड़ टैक्स पेयर्स थे, अब 7.78 करोड़ टैक्स पेयर्स हो गए हैं । फास्टैग के द्वारा जहां एक ट्रक 300 किलोमीटर चलती थी, अब वह 600 किलोमीटर चल रही है । ईपीएफओ में जहां 11.8 करोड़ लोग थे, आज के समय करीब 28 करोड़ लोग हो गए हैं । इस प्रकार से फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी जो चल रही है, उससे इकोनॉमी में बहुत सुधार आ रहा है । हमारा टैक्स कलैक्शन बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है । लेकिन मुझे बहुत दु:ख है कि अभी भी इकोनॉमी में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं और कुछ ऐसे लोग हैं, जो फॉर्मलाइजेशन में विश्वास नहीं करते हैं ।

16.04 hrs (Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे झारखंड में ही छापे के बाद एक बड़ी दु:खद घटना निकल कर आई है, जहां शराब व्यापार में लिप्त एक राज्य सभा के सांसद के घर में 350 करोड़ रुपये से ज्यादा का कैश मिला है । जहां हम लोग एक ओर, भारतीय जनता पार्टी के हर कोई सदस्य का यह प्रयास रहा है कि इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हो, इकोनॉमी में टैक्स कलैक्शन बढ़े, देश में सुधार आए, वैसे ही अगर आप हमारे विपक्ष की ओर देखें तो इनका कैश का व्यापार चलता चला जा रहा है और बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रहा है । अभी भी ये लोग टैक्स के दायरे में आने को तैयार नहीं हैं । इनकी जो लूट है, खासकर झारखंड में, इनकी जो लूट है, वह निरंतर चलती चली जा रही है । जहां ईडी, सीबीआई, आईटी की छापेमारी चलती चली जा रही है, वहां एक नहीं अनेकों ऐसे लोग निकल कर आ रहे हैं, जिनमें अधिकारी भी हैं, नेता भी हैं और एक बहुत बड़े नेता हैं, जिनको 6 बार बुलाया गया है । ईडी ने उनको 6 बार बुलाया है, लेकिन दु:खद बात है कि इन लोगों की जो लूट है, इनफॉर्मल इकोनॉमी में इन लोगों का कैश में जो कारोबार चल रहा है, उससे बचने के लिए ईडी ने उनको बुलाया भी है ।

He has not presented himself in front of the ED.

माननीय सभापति महोदया, इसी तरीके से हम लोगों का प्रयास है कि कस्टम्स एंड एक्साइज़ में, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि हम लोगों को डायनैमिकली एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, अगर हम लोगों को प्रॉविज़नल टैक्स कलेक्शन करना पड़े, तो सरकार के पास उसका अधिकार होना चाहिए, on a provisional basis for up to 75 days to adjust to dynamic conditions चाहे कहीं डम्पिंग हो जाए या कहीं पर तेजी से भाव बढ़ रहे हों, तो उसके लिए हम राहत दे सकें । इसलिए हम लोगों को ये पावर्स सरकार को देने चाहिए । इस प्रॉविज़नल कलेक्शन ऑफ टैक्सेज के द्वारा हम लोग ये पावर्स सरकार को दे रहे हैं ।

इस तरह से, जो लोग कैश का कारोबार कर रहे हैं, हम लोगों को उन पर रोक लगानी चाहिए, छापा मारकर उन लोगों को रोकना चाहिए । यदि ऐसा आप करेंगे, तो झारखण्ड में और बहुत सारे लोग निकलकर आएंगे ।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यही गुज़ारिश करूँगा कि ईडी के द्वारा, आईटी के द्वारा और भी छापेमारी हो ताकि जहाँ कोयला, भू-माफिया, शराब, बालू आदि का अवैध कारोबार चल रहा है, काले करतूत चल रहे हैं, आप इन पर छापेमारी कीजिए और अभी जो बिज़नेस कैश में चल रहे हैं, उनको टैक्स के दायरे में लाइए । हम सब को राहत दिलवाइए ताकि हम लोग एक विकसित भारत बना सकें । माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जल्द से जल्द सबको हर प्रकार की सुविधा मिले और एक विकसित भारत का निर्माण हो । जिस तरह से, अभी हम लोग जीएसटी के बिल में अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, कस्टम्स और एक्साइज़ ड्यूटी में अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, हम लोगों के प्रयास से तो यह होता ही रहेगा, लेकिन मैं विपक्ष के साथियों से भी यही विनती करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा कि ऐसे अवैध कारोबार आप छोड़िए, टैक्स के दायरे में आइए ताकि हम लोग मिल जुलकर एक विकसित भारत बना सकें ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Thank you, Chairperson Madam. I stand here to support the Provisional Collection of Taxes Bill, 2023 on behalf of the YSR Congress Party.

Before I speak in support of the Bill, I would also like to take this opportunity to talk about some of the ongoing issues regarding taxation and collection of taxes and provide some suggestions regarding the same.

The first point is regarding the remarkable surge in Centre?s tax revenue collection and the need for its strategic allocation. I would like to highlight that in 2022, the Central Government has observed an extraordinary 303 per cent surge in tax revenue over the past 12 years, escalating from Rs. 6.2 lakh crore in the financial year 2010 to Rs. 25.2 crore in the financial year 2022.

The second point is regarding high tax burden on middle class. In the current context, the middle-class population in our country would welcome a reduction in the tax burden. Presently, the rich constitute a small proportion, and the majority of India?s population remains tax exempt, leaving the middle-income group with a substantial tax burden and limited returns.

The third point is regarding enhancing the Public Provident Fund. The unchanged interest rate of the Public Provident Fund, PPF, demands immediate attention, having remained at 7.1 per cent since April 2020, falling short of the 7.9 per cent recommended by the Reserve Bank of India, RBI.

Another point is regarding expanding the tax base for inclusive growth. The increase in population has led to a growth in the workforce. However, the income tax base has not seen a corresponding expansion, necessitating attention. While the absolute number of Income Tax Return filers in India has risen, a closer examination of the data from the Ministry of Finance in Lok Sabha for financial year 2023 reveals a comparatively lower number of individuals who have actually paid income tax, especially when compared to the figures from financial year 2020. To achieve this inclusive growth, the Government should consider reducing tax rates by broadening the tax net. A scenario where a larger population files Income Tax Returns and contributes to income tax payments could lead to a more prosperous country and a more even distribution of the tax burden among assesses.

This, in turn, could result in substantial reductions in tax rates providing individuals with more disposable income for spending and contributing to the accelerated growth of the economy. Taking steps to effectively harness this workforce can contribute significantly to the GDP.

Though the hon. Finance Minister expressed her commitment to addressing the challenges faced by the middle-class while presenting the Budget 2023-2024,

significant tax burdens persist among the population. So, in conclusion, from YSR Congress Party under the dynamic leadership of our hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y. S. Jagan Mohan Reddy Garu, I appeal to the Ministry to consider implementing the suggestions from our Party as I had presented today as these reforms will undoubtedly contribute to the further growth of our economy.

Thank you very much, Madam.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Thank you, Madam.

I would like to thank both the Members who have spoken on the topic. I appreciate the hon. Member Jayant Sinha for having given a complete picture of what we are doing through this Provisional Collection of Taxes Bill, and I also appreciate Dr. Sathyavathi for having given a picture of how we can take this forward and the suggestions that she has put forth on behalf of her Party. This is certainly something which I will have the Ministry go through. I hope this is not taken as an assurance, but I will value her inputs and take it forward.

So, with these words as reply to the two hon. Members who spoke, I request that the House pass the Bill.

माननीय सभापति**:** प्रश्न यह है :

?कि सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क के अधिरोपण या उसमें वृद्धि से संबंधित विधेयक के उपबंधों को सीमित अवधि के लिए तुरंत प्रभावी करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

माननीय सभापति **:** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

?कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

<u>खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए ।</u>

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।</u>

माननीय सभापति **:** मंत्री जी, अब आप यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

?That the Bill be passed.?

माननीय सभापति **:** प्रश्न यह है :

?कि विधेयक पारित किया जाए ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u> ।

———

माननीय सभापति **:** आइटम नंबर **?** 32, श्री नित्यानन्द राय जी ।

? (व्यवधान)

<u>16.14 hrs</u>